नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 239
दि. 02.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'दिव्यास्त्र एमके-1' ने दिखाई ताकत, स्वदेशी ड्रोन हथियार प्रणाली के सफल परीक्षण से बढ़ी भारत की मारक क्षमता

नई दिल्ली। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए सामरिक मंडराने वाले आयुध मंच 'दिव्यास्त्र एमके-1' का सफल परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमताओं को नई मजबूती दी है। राजस्थान के जोधपुर में आयोजित इस परीक्षण के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों की मौजूदगी में मानवरहित हवाई आयुध प्रणाली ने अपने सभी प्रमुख परिचालन मानकों पर सफल प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि को न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की युद्धक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को भी बड़ी गति देने वाला कदम माना जा रहा है।

परीक्षण के दौरान 'दिव्यास्त्र एमके-1' को वाहन पर स्थापित मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य यह साबित करना था कि युद्धक्षेत्र की बदलती परिस्थितियों में इस प्रणाली को कम समय में किसी भी स्थान पर तैनात कर प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। परीक्षण में ड्रोन की गतिशीलता, लक्ष्य पहचान क्षमता, निगरानी दक्षता और सटीक प्रहार की क्षमता का भी सफल प्रदर्शन किया गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में ऐसी प्रणालियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई करने में सक्षम होती हैं।

'दिव्यास्त्र एमके-1' को विशेष रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोही अभियान और सटीक हमले जैसे सैन्य कार्यों के लिए विकसित किया गया है। यह केवल एक ड्रोन नहीं, बल्कि एक पूर्ण

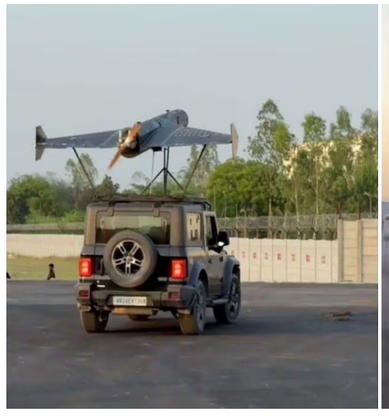

सामरिक हथियार प्रणाली है जो लक्ष्य क्षेत्र में लंबे समय तक मंडरा सकती है, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है और आवश्यक होने पर तुरंत हमला भी कर सकती है। इस क्षमता के कारण इसे आधुनिक युद्ध की भाषा में 'लॉइटरिंग म्यूनिशन' यानी मंडराने वाला आयुध कहा जाता है।

रक्षा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार वर्तमान समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक मिसाइलें और लड़ाकू विमान जहां अत्यधिक महंगे साबित होते हैं, वहीं ऐसे स्मार्ट ड्रोन कम लागत में अधिक प्रभावी परिणाम देने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अब लॉइटरिंग म्यूनिशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन प्रणालियों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। भारत द्वारा विकसित 'दिव्यास्त्र एमके-1' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी परिचालन क्षमता है। 'दिव्यास्त्र एमके-1' लगभग 500 किलोमीटर तक की दूरी तक प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है और लगातार पांच घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी गति 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे यह तेजी से लक्ष्य तक पहुंचकर कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा यह 15 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिससे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए इसे अलग-अलग आयुधों और उपकरणों से लैस किया जा सकता है।

दिव्यास्त्र की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसमें प्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित तकनीक है। एआई की मदद से यह लक्ष्य की पहचान, निगरानी और प्रहार जैसे कार्यों को अधिक सटीकता के साथ अंजाम दे सकता है। इसमें समूह-संचालन या 'स्वॉर्म' क्षमता भी मौजूद है, जिसके माध्यम से कई ड्रोन एक साथ समन्वित तरीके से अभियान चला सकते हैं। भविष्य के युद्धों में यह क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भ्रमित करना और कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करना संभव हो सकेगा।

यह प्रणाली विद्युत-प्रकाशीय और अवरक्त सेंसरों से लैस की जा सकती है, जिससे दिन और रात दोनों परिस्थितियों में निगरानी एवं लक्ष्य पहचान संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें संचार पुनर्प्रेषण प्रणाली भी जोड़ी जा सकती है, जिससे युद्धक्षेत्र में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाया जा सके। मिशन की आवश्यकता के अनुसार इसके आयुध विन्यास को भी बदला जा सकता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों में उपयोगी साबित होता है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 'दिव्यास्त्र एमके-1' जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे। अब तक ऐसी उन्नत प्रणालियों के लिए विदेशी तकनीक और आयात पर निर्भरता रहती थी, लेकिन स्वदेशी विकास के कारण न केवल लागत कम होगी बल्कि भारतीय सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक को लगातार उन्नत भी किया जा सकेगा।

जोधपुर में हुए सफल परीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब आधुनिक ड्रोन युद्ध प्रणाली के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के संघर्षों में मानवरहित हथियार प्रणालियां निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, 'दिव्यास्त्र एमके-1' का सफल परीक्षण भारतीय रक्षा क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह सफलता न केवल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की उपस्थिति को भी और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

नीट पेपर लीक मामले में फिलहाल राहत नहीं, सीबीटी मोड की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक टाली

नई दिल्ली। देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने नीट-यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित कराने और कथित पेपर लीक की घटनाओं के मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जुलाई में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। यह मामला राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिका में मांग की गई थी कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगामी परीक्षा को पारंपरिक पेन-पेपर मोड के बजाय कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित किया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना कम होगी और परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनेगी।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने मामले की

सुनवाई करते हुए कहा कि यह विषय पहले से विचाराधीन अन्य याचिकाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस स्तर पर अलग से कोई आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। अदालत ने संकेत दिया कि पूरे मामले की व्यापक सुनवाई जुलाई में की जाएगी, जहां सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने अदालत को बताया कि वे फिलहाल केवल उस मांग पर जोर दे रहे हैं जिसमें नीट परीक्षा को सीबीटी मोड में आयोजित करने की बात कही गई है। उनका कहना था कि तकनीकी माध्यम से परीक्षा कराने से परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी। हालांकि अदालत इस दलील से तत्काल सहमत नहीं हुई।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत पूर्व में भी इसी प्रकार की मांगों से जुड़ी याचिकाओं पर विचार कर चुकी है और कई मामलों में ऐसी याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है। अदालत की इस टिप्पणी को याचिकाकर्ता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत मिला कि शीर्ष अदालत फिलहाल परीक्षा प्रक्रिया में तत्काल बदलाव के पक्ष में नहीं है।

इस निर्णय का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रणाली में कराने की मांग कर रहे थे। अदालत द्वारा सुनवाई जुलाई तक टाल दिए जाने के कारण 21 जून को प्रस्तावित परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के आरोपों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। नीट-यूजी से जुड़े विवादों ने भी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन तंत्र पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसी पृष्ठभूमि में परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने की मांग लगातार उठती रही है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन देशभर में लाखों छात्रों के लिए एक साथ ऐसी परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूत तकनीकी आधारभूत संरचना और व्यापक तैयारी की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इस विषय पर नीति स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श जरूरी माना जा रहा है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि नीट परीक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। अब सभी की निगाहें जुलाई में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां शीर्ष अदालत पेपर लीक, परीक्षा सुरक्षा और सीबीटी मोड जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से विचार कर सकती है। तब तक 21 जून को प्रस्तावित नीट परीक्षा अपने निर्धारित स्वरूप में आयोजित होने की संभावना बनी हुई है।

मणिपुर में छह नागा लोगों के कथित अपहरण से बढ़ी चिंता मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने अमित शाह से मांगा हस्तक्षेप

कोहिमा। मणिपुर में छह नागा समुदाय के लोगों के कथित अपहरण की घटना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिंता और तनाव बढ़ा दिया है। इस गंभीर मामले को लेकर नागालैंड के मुख्यमंत्री Neiphiu Rio ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर अपहृत लोगों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री रियो ने स्पष्ट किया कि यह केवल छह व्यक्तियों के अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि इससे पूरे नागा समाज में असुरक्षा और चिंता का माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि स्थिति को और अधिक संवेदनशील बनने से रोकना आवश्यक है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की थी और नागा समुदाय की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया था। इसके बाद 30 मई को उन्होंने United Naga Council के अध्यक्ष एन.जी. लोहरी को लिखे पत्र में इस संवाद की जानकारी

साझा की। रियो ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि अपहृत लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए, अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर ले रही है। शाह ने संबंधित सुरक्षा और जांच एजेंसियों को निर्देश देने का भरोसा दिया है ताकि अपहृत व्यक्तियों का जल्द पता लगाया जा सके और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो सके।

रियो ने कहा कि केंद्र सरकार की सक्रियता से नागा समुदाय को राहत मिली है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने केवल गृह मंत्री तक ही मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव और Intelligence Bureau (आईबी) के निदेशक से भी सीधे संपर्क किया। उन्होंने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की गंभीरता से अवगत कराया और त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया।

रियो के अनुसार दोनों अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सुरक्षा एजेंसियां मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपहृत लोगों की तलाश के लिए समन्वित अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस घटना के बाद नागा सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में गहरी चिंता देखी जा रही है। नागा समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों ने अपहरण की घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपहृत लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि ऐसे घटनाक्रम क्षेत्र में शांति और विश्वास के माहौल को प्रभावित करते हैं।

मणिपुर पहले से ही जातीय और सामाजिक तनावों से जूझ रहा है। ऐसे में छह लोगों के कथित अपहरण की घटना ने एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह मामला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका संबंध सीधे समुदायों के बीच विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि अपहृत लोगों की शीघ्र और सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित नहीं हुई तो इसका असर व्यापक सामाजिक माहौल पर पड़ सकता है। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

फिलहाल नागालैंड और मणिपुर दोनों राज्यों में लोग सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं और अपहृत छह नागा नागरिकों की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भाजपा पर बरसीं ममता, बोलीं- पुलिस के सहारे टीएमसी को तोड़ने की हो रही कोशिश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के जनप्रतिनिधियों को पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है और राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने की रणनीति अपनाई जा रही है।

पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल को जानबूझकर तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक मुकाबला करने के बजाय जांच एजेंसियों, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाओं का उपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार यह केवल टीएमसी पर हमला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है।

ममता बनर्जी ने विशेष रूप से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के प्रमुख नेताओं की छवि खराब करने और उन्हें राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया

जा रहा है। ममता ने कहा कि विपक्ष की मजबूत आवाज को दबाने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को लेकर भी प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ममता का कहना था कि यदि किसी कारणवश प्रशासन उस स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना चाहता था तो उसे कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर पार्टी को विरोध प्रदर्शन से रोकने की कोशिश की गई।

ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोलकाता में पार्टी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो वह अपना आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह स्वयं दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगी और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को शांतिपूर्ण विरोध की आवाज दबाने का अधिकार नहीं है।

अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने फेरीवालों और छोटे कारोबारियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी समुचित पुनर्वास योजना के फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों और छोटे व्यापारियों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का दायित्व केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों के जीवन और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक कार्रवाई और धमकियों के बावजूद टीएमसी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ी तल्खी के बीच ममता बनर्जी का यह बयान राज्य की राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। एक ओर भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक निर्णयों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक विवाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

संपादकीय

निकाय चुनाव नतीजों से बढ़ा आप का भरोसा

सही मायने में पंजाब के हालिया स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों के आधार पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक निष्कर्ष तो नहीं निकाले जा सकते। हां, लेकिन इन परिणामों से महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत जरूर मिलते हैं। निस्संदेह, लोकतंत्र की इस छोटी इकाई, नगर निकाय चुनावों में राज्य स्तर का व्यापक परिदृश्य तो नहीं उभरता, बल्कि स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में निर्णायक भूमिका जरूर निभाते हैं। वैसे पिछले ट्रेंड के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसे चुनावों में राज्य के सत्ताधारी दल को लाभ निश्चित रूप से मिलता है। इसका कारण यह भी है कि प्रभावी व संपन्न लोग सत्तारूढ़ दल के करीब आना चाहते हैं। मतदाता यह मानकर चलते हैं कि विकास निधि और प्रशासनिक सहायता उन क्षेत्रों में सहज व सरलता से पहुंचती है, जहां सत्तारूढ़ दल से जुड़े प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। इस तथ्य की पुष्टि एक बार फिर से हुई है, जब इन निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही जबकि भाजपा और अकाली दल निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रह गए। वास्तव में इन आंकड़ों को सावधानी से देखना चाहिए। दरअसल, स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कुल मतदान का प्रतिशत 64 फीसदी रहा, लेकिन नगर निगमों में यह भागीदारी 60 फीसदी रही, जो बड़े शहरों में मतदाता की सुस्ती को दर्शाता है।

सही मायने में स्थानीय निकाय चुनावों में आमतौर पर मतदाताओं की भागीदारी असमान और कम रही है। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में मतदान आमतौर पर अधिक होता है और राजनीतिक मुद्दे व्यापक होते हैं। इसके बावजूद, यह चुनाव निष्कर्ष विपक्ष के लिए चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाता है। पंजाब में पांव पसारते नशीली दवाओं के कारोबार, अपराध, कानून व्यवस्था और सरकार की शासन संबंधी नीतियों को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना के बावजूद, विपक्षी दल जनता की असंतुष्टि को वोटों में तब्दील करने में विफल ही रहे हैं। कांग्रेस गुटबाजी और नेतृत्व की अनिश्चितता से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर शिअद अभी भी बेअदबी विवाद और किसान आंदोलन के राजनीतिक नतीजों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि, भाजपा राज्य के चुनावी परिदृश्य में अभी भी एक मामूली खिलाड़ी ही साबित हुई है, मगर ऐसा लगता है कि उसने 2027 के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। जट सिख केवल सिंह ढिल्लों की पंजाब भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति महत्वपूर्ण है। भाजपा ने अपने पारंपरिक शहरी-हिंदू आधार से आगे बढ़ने के प्रयास का संकेत दिया है। निस्संदेह, अभी विधानसभा चुनाव का रास्ता खासा लंबा है। लेकिन फिलहाल, आम आदमी पार्टी ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी एकजुटता और दिशा की तलाश में लगा हुआ है।

ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता से थमेगी महंगाई

> अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा। इससे देश में सभी चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। दरअसल, इसकी वजह अधिकांश पेट्रो प्रोडक्ट्स के लिए आयातों पर निर्भरता है। बढ़ती महंगाई से निपटने का स्थायी उपाय ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है।

स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई दौर नहीं आया जब देश में चीजें व्यापक रूप से सस्ती हुई हों। महंगाई की समस्या मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग के जीवन में लगातार बनी रही है। इसका एक प्रमुख कारण हमारी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था है। आयातों का भुगतान डॉलर में करने तथा बजट घाटे के दबाव के कारण आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ती है। साथ ही, कच्चे माल का आयात भी महंगा पड़ता है, जिसके कारण उससे निर्मित तैयार उत्पादों की लागत और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं।

देश का आम आदमी लंबे समय से महंगाई की मार झेलता आया है, जबकि सरकारें समय-समय पर उस पर नियंत्रण का आश्वासन देती रही हैं। कोविड-19 के बाद महंगाई नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने कठोर साख नीति अपनाई, जिससे ऋण महंगे हो गए और निवेश तथा आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे। बाद में आधिकारिक आंकड़ों में थोक महंगाई दर शून्य से नीचे तथा खुदरा महंगाई दर सुरक्षित सीमा के भीतर दिखाई गई, किंतु आम जनता को बाजार में वस्तुएं वास्तव में सस्ती नहीं मिलीं। इसका एक कारण यह भी रहा कि लागत में आई कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बजाय कई बार बिचौलियों और फुटकर व्यापारियों के अतिरिक्त लाभ में बदल गया।

देश महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता से राहत की उम्मीद कर ही रहा था। रेपो दरों में कटौती का दौर भी थम गया था और अपेक्षा की जा रही थी कि घरेलू तथा विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छुएगा। किंतु अचानक एक युद्ध ने ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख मार्ग, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाधित हो गया। इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने की आशंकाएं फिर से प्रबल हो गईं और आम जनता की चिंताएं बढ़ने लगीं।

वर्तमान स्थिति यह है कि देश में आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में मूल्य कई बार बढ़ाए गये हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित रहने के बावजूद देश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई हैं। इस निरंतर वृद्धि से पेट्रोल-डीजल आम उपभोक्ता के लिए बेहद महंगा हो रहा है। यद्यपि सरकार आश्वासन देती रही है कि देश के पास लगभग 75 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है, जिससे आपूर्ति बाधित नहीं होगी और पेट्रोल पंपों पर सामान्य स्थिति बनी रहेगी, फिर भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। सरकार का तर्क है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के दौरान घरेलू बाजार में पेट्रोल व डीजल के दाम लंबे समय तक स्थिर रखे गए, जिससे पेट्रोलियम कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी घाटे की भरपाई के लिए ईंधन कीमतों को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। वहीं, व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने होटल, ढाबों और खाद्य व्यवसायों की लागत बढ़ा दी है। परिणामस्वरूप भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति प्रभावित हुई है और खाद्य बाजार में मंदी का माहौल बन गया है।

उधर, वित्त मंत्री के अनुसार उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और रुपये के अवमूल्यन ने आयात लागत को और बढ़ा दिया है। सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाकर राजस्व का नुकसान उठाया है, किंतु ऊर्जा आयात पर निर्भरता और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बैंकों को कारोबार-अनुकूल ऋण विकल्प विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित सीएनजी भी महंगी होती जा रही है, जिससे परिवहन लागत बढ़ रही है। विपक्ष इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बताता है, जबकि सरकार का तर्क है कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और ऊर्जा आपूर्ति संकट जैसे कारण हैं, जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हैं। बढ़ती महंगाई से निपटने का स्थायी समाधान देश को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातों पर निर्भर है, इसलिए वैश्विक संकटों और युद्धों का सीधा प्रभाव महंगाई के रूप में देश को झेलना पड़ता है। यदि अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुख बनाया जाता और लघु एवं कुटीर उद्योगों को व्यापक स्तर पर विकसित कर उनके निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाई जाती, तो विदेशी निर्भरता कम हो सकती थी।

इसी प्रकार, देश में उपलब्ध संभावित तेल एवं ऊर्जा संसाधनों के पर्याप्त दोहन पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ऊर्जा आयात पर निर्भरता बनी रही। परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। समाधान यह है कि भारत उत्पादन, ऊर्जा और निर्यात के क्षेत्र में अधिक स्वावलंबी बने। जितना अधिक स्वावलंबन होगा, उतनी ही आयातों पर निर्भरता घटेगी और महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना आसान होगा।

प्रेरणा

एक उत्तर जिसने बदल दी तकदीर

जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन वही क्षण भविष्य की दिशा तय कर देते हैं। किसी व्यक्ति के कुछ शब्द, उसका व्यवहार या किसी परिस्थिति में लिया गया निर्णय उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा के बल पर असंभव प्रतीत होने वाली ऊंचाइयों को छुआ है। महान कथाकार और संत ईसप का जीवन भी इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन इस बात की प्रेरणा देता है कि सच्चाई और आत्मविश्वास से दिया गया एक उत्तर भी व्यक्ति की तकदीर बदल सकता है।

ईसप का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय समाज में गुलामों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं था और वे अपने मालिकों की इच्छा पर निर्भर रहते थे। अधिकांश लोग ऐसी परिस्थितियों में अपने सपनों को त्याग देते थे, लेकिन ईसप का व्यक्तित्व अलग था। वे बचपन से ही जिज्ञासु, समझदार और संस्कारवान थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने भीतर सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों को जीवित रखा। वे मानते थे कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके विचारों और आचरण से होती है।

जैसे-जैसे वे बड़े हुए, उनकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार-कुशलता लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी। हालांकि वे गुलाम थे, लेकिन उनके विचार स्वतंत्र थे। वे हर परिस्थिति को समझदारी से देखते और किसी भी समस्या का उत्तर शांत मन से खोजते थे। यही गुण आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बने। एक दिन उनके मालिक ने निर्णय लिया कि वह उन्हें अन्य दो गुलामों के साथ बाजार में बेच देगा। बाजार में उस समय गुलामों की खरीद-बिक्री आम बात थी। खरीदार यह देखते थे कि कौन-सा गुलाम अधिक मेहनती, आज्ञाकारी और उपयोगी है। उसी दिन वहां जॉनसन नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी पहुंचे। वे केवल श्रमिक नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसमें समझदारी और विश्वासयोग्यता हो।

जॉनसन ने पहले गुलाम से पूछा, "यदि मैं तुम्हें खरीदूं तो तुम क्या करोगे?" उसने तुरंत उत्तर दिया, "स्वामी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा।" यह उत्तर सुनकर जॉनसन ने सिर हिलाया और दूसरे गुलाम की ओर बढ़े। दूसरे ने भी कहा, "मैं और मेरा साथी मिलकर आपका सारा काम संभाल लेंगे।" दोनों उत्तर विनम्र थे, लेकिन उनमें कोई विशेष बात नहीं थी। वे केवल मालिक को खुश करने के लिए कही गई सामान्य बातें थीं। अब जॉनसन ने ईसप की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने वही प्रश्न दोहराया। ईसप ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "जब ये दोनों आपका सारा काम कर देंगे, तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा?" यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जॉनसन ने इस उत्तर में कुछ और देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह युवक केवल बोलने में चतुर नहीं, बल्कि परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देखने की क्षमता रखता है।

ईसप के उत्तर में आत्मविश्वास था, लेकिन अहंकार नहीं था। उसमें हास्य था, लेकिन असम्मान नहीं था। यही संतुलन उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। जॉनसन उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उन्होंने एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, "यदि मैं तुम्हें खरीद लूं तो क्या तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे?"

यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। कोई भी गुलाम यह जानता था कि ऐसा उत्तर उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अधिकांश लोग मालिक को प्रसन्न करने के लिए तुरंत हां कह देते, लेकिन ईसप ने वही कहा जो उनके हृदय में था। उन्होंने उत्तर दिया, "मालिक, आप मुझे खरीदें या न खरीदें, मेरी ईमानदारी मेरे साथ ही रहेगी।"

यह सुनकर जॉनसन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। यह केवल एक उत्तर नहीं था, बल्कि एक चरित्र की घोषणा थी। ईसप ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी ईमानदारी किसी व्यक्ति, पद या लाभ की मोहताज नहीं है। वह उनके जीवन का स्थायी हिस्सा है। ऐसे शब्द केवल वही व्यक्ति कह सकता है जिसके भीतर सच्चाई गहराई तक बसी हो।

जॉनसन ने तुरंत निर्णय लिया और ईसप को खरीद लिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह युवक साधारण नहीं है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके हाथों की ताकत नहीं, बल्कि उसके चरित्र की दृढ़ता है। यही गुण भविष्य में उसे महान बनाएंगे।

समय बीतता गया और ईसप ने अपने जीवन में निरंतर प्रगति की। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, अनुभव प्राप्त किए और अपनी बुद्धिमत्ता को समाज के हित में उपयोग किया। धीरे-धीरे वे एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाने लगे। उनकी रचनाओं में जीवन के गहरे सत्य छिपे होते थे। वे सरल कहानियों के माध्यम से ऐसी शिक्षाएं देते थे जो हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती थीं। उनकी कथाएं आज भी संसार के अनेक देशों में पढ़ी जाती हैं और बच्चों से लेकर विद्वानों तक सभी को प्रेरणा देती हैं।

ईसप की सफलता का रहस्य केवल उनकी प्रतिभा नहीं थी। प्रतिभा तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन चरित्र सभी के पास नहीं होता। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। यही कारण था कि एक गुलाम का जीवन जीने वाला व्यक्ति आगे चलकर विश्वविख्यात साहित्यकार और संत बना।

उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अवसर अचानक नहीं आते। अवसर अक्सर हमारे व्यवहार, विचार और चरित्र से पैदा होते हैं। यदि ईसप उस दिन भी अन्य गुलामों की तरह केवल मालिक को खुश करने वाली बातें कहते, तो शायद वे जॉनसन का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप सत्य और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। वही उत्तर उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। आज के समय में भी यह प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में लोग सफलता पाने के लिए अनेक शॉर्टकट खोजते हैं। कुछ लोग झूठ, दिखावा और चापलूसी का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे जल्दी आगे बढ़ जाएंगे।

बालेन्द्र शाह ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन को निमंत्रित कर अपनी जगहँसाई करवा ली है

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहा पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की चौंकाने वाली और कई मायनों में अपरिपक्व बयानबाजी बनी है। संसद में उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। हालात इतने असहज हो गए कि कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। और विडंबना देखिए, भारत को घेरने की कोशिश में दिया गया बयान नेपाल में ही प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ गया। विपक्ष, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राजदूत और सीमा विशेषज्ञ तक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सबूत, स्पष्टीकरण, यहां तक कि माफी की मांग होने लगी। सीमा विवाद पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाने के बजाय बालेन्द्र शाह की टिप्पणियां ऐसी साबित हुईं जिन्होंने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने दोनों देशों से तथ्यों का अध्ययन कर मित्रवत तरीके से विवाद सुलझाने की अपील की। उधर, नेपाल में विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने बालेन्द्र शाह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और अन्य नेताओं ने संसद के अभिलेखों से बयान हटाने की मांग की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य और दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री की बातों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया। इस प्रकार बालेन्द्र शाह का बयान भारत से अधिक नेपाल के भीतर ही विवाद का विषय बन गया।

दरअसल, सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र हैं। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख दर्रे के नीचे स्थित स्रोतों से होता है और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कालापानी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। यही मूल विवाद दोनों देशों के दावों की जड़ में है। हम आपको बता दें कि विवाद को हाल में उस समय नया मोड़ मिला जब नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लगातार संचालित हो रही है और यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि एकतरफा तरीके से क्षेत्रीय दावों का विस्तार न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही स्वीकार्य है।

उधर, बालेन्द्र शाह के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। मंत्रालय के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों की कमी, दशगजा क्षेत्र और सीमापार भूमि उपयोग जैसी व्यावहारिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दोनों ओर के लोग एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत, तकनीकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सबसे अधिक हैरानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उस सुझाव पर हुई जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी की बात उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान सीमाओं की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव न केवल व्यावहारिक दृष्टि से कमजोर माना गया बल्कि नेपाल के भीतर भी इसे अपरिपक्व और अनावश्यक बताया गया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हमेशा द्विपक्षीय ढांचे में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में तीसरे पक्ष को बीच में लाने की बात कूटनीतिक परंपराओं और स्थापित समझ से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील और पूर्णतः द्विपक्षीय विषय में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव बालेन्द्र शाह की कूटनीतिक नासमझी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसने कई जानकारों को हैरान कर दिया। भारत दशकों से स्पष्ट करता आया है कि वह अपने किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल को स्वीकार नहीं करता, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चीन का हो या नेपाल का। ऐसे में ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर बुलाने का प्रस्ताव शुरू से ही अव्यावहारिक और वास्तविकताओं से कटा हुआ नजर आया।

अभियान

विघ्नहर्ता की साधना और आत्मशक्ति का महापर्व

भारतीय संस्कृति में व्रत और पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। हमारी सनातन परंपरा में प्रत्येक व्रत के पीछे कोई न कोई गहरा दार्शनिक संदेश छिपा हुआ है। इन्हीं पवित्र व्रतों में संकष्टी चतुर्थी का विशेष स्थान है। भगवान गणेश को समर्पित यह व्रत श्रद्धा, संयम, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। यह केवल संकटों को दूर करने की कामना का दिन नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर भी है। सदियों से भारतीय जनमानस इस व्रत को अपार श्रद्धा और विश्वास के साथ करता आया है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकारी देवता माना जाता है, इसलिए उनकी उपासना से जुड़ा यह व्रत जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला तथा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है।

'संकष्टी' शब्द संस्कृत के 'संकट' अथवा 'कष्ट' शब्द से बना है। इसका तात्पर्य उन कठिनाइयों और बाधाओं से है जो मनुष्य के जीवन में समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। जब यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है, तब इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है तथा जीवन के विविध प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों में लाखों श्रद्धालु इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान गणेश से अपने तथा परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार का आरंभ हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, गणेश पूजन के बिना कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता। इसका मूल कारण यह है कि गणेश जी बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता के प्रतीक हैं। वे जीवन में आने वाले अवरोधों को दूर कर व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इसी भावना को और अधिक गहराई से आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है।

इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान भी छिपा हुआ है। आधुनिक जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार की चिंताओं, तनावों और प्रतिस्पर्धाओं से घिरा हुआ है। निरंतर भागदौड़, भौतिक उपलब्धियों की होड़ और मानसिक दबाव व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देते हैं। ऐसे समय में संकष्टी चतुर्थी जैसे व्रत व्यक्ति को स्वयं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उपवास, ध्यान, जप और पूजा के माध्यम से व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहरी संसार से हटकर अपने अंतर्मन की ओर लौटता है। यही प्रक्रिया मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का आधार बनती है।

संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा में दूर्वा, लाल पुष्प, चंदन, धूप, दीप, मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दूर्वा और मोदक भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इनका विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु दिनभर उपवास रखते हैं और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते हैं। कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार ग्रहण करते हैं। व्रत का समापन चंद्र दर्शन के पश्चात किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने और गणेश जी की आरती के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मसंयम का अभ्यास भी है।

उपवास का महत्व भारतीय दर्शन में अत्यंत व्यापक है। सामान्यतः लोग उपवास को केवल भोजन त्यागने से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तविक अर्थ में उपवास का तात्पर्य है— अपने भीतर स्थित दिव्यता के निकट रहना। जब व्यक्ति भोजन, क्रोध, लालसा और इंद्रियों की चंचलता पर नियंत्रण स्थापित करता है, तब उसका मन अधिक शांत और केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि योग और आयुर्वेद में भी समय-समय पर उपवास को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत व्यक्ति को संयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से प्राप्त होती है।

इस व्रत से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय देवताओं और मनुष्यों के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो गईं। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समाधान पूछा। तब भगवान शिव ने कहा कि समस्त विघ्नों को दूर करने की शक्ति केवल गणेश जी में है। देवताओं ने भगवान गणेश की आराधना की और चतुर्थी का व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने सभी संकटों का नाश कर दिया। तभी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं।

एक अन्य प्रसिद्ध कथा चंद्रमा से संबंधित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश का स्वरूप देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज समाप्त होने लगा। तब चंद्रमा ने पश्चाताप किया और गणेश जी की आराधना की। अंततः गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे क्षमा प्रदान की। इसी घटना के कारण संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का परिणाम सदैव दुखद होता है, जबकि विनम्रता और पश्चाताप व्यक्ति को पुनः सम्मान दिला सकते हैं।

यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संकष्टी चतुर्थी का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या बाहरी संकट नहीं, बल्कि मानसिक असंतुलन है। तनाव, अवसाद, चिंता और असुरक्षा की भावना समाज में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में यह व्रत व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। दिनभर का उपवास शरीर को विश्राम देता है, मंत्रजप मन को स्थिर करता है और पूजा-अर्चना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस प्रकार यह व्रत शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम बन जाता है।

कई लोग आज संकष्टी चतुर्थी को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवनशैली सुधारने के एक अवसर के रूप में भी देखते हैं। इसे एक प्रकार का मासिक आत्ममंथन दिवस कहा जा सकता है। पूरे महीने की व्यस्तताओं के बीच यह दिन व्यक्ति को रुककर स्वयं को देखने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देता है। उपवास के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। वह समझता है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है। यही अभ्यास जीवन में धैर्य और परिपक्वता विकसित करता है। भगवान गणेश का स्वरूप भी गहन प्रतीकात्मक अर्थों से भरा हुआ है। उनका विशाल मस्तक व्यापक चिंतन का संदेश देता है। बड़े कान अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं। लंबी सूंड परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता को दर्शाती है। उनका वाहन मूषक इच्छाओं और चंचल मन का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इन सभी गुणों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यह व्रत अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और देश के अनेक राज्यों में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचते हैं। यद्यपि क्षेत्रीय परंपराओं में कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन व्रत का मूल भाव हर जगह एक ही रहता है— श्रद्धा, संयम और आत्मशुद्धि। वास्तव में संकष्टी चतुर्थी केवल संकटों से मुक्ति का पर्व नहीं है। यह जीवन को संतुलित, अनुशासित और सकारात्मक बनाने का आध्यात्मिक अभियान है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

प्रधानमंत्री के दौरे ने बदली मनपा की प्राथमिकताएं, समिति गठन पर लगा विराम; सूरत नगर निगम की दूसरी जनरल बैठक टलने के आसार

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जून को प्रस्तावित सूरत दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन, सूरत महानगरपालिका (एसएमसी), पुलिस विभाग और सत्तारूढ़ भाजपा संगठन पूरी तरह जुटे हुए हैं। इस व्यस्तता का सीधा असर अब नगर निगम के नियमित प्रशासनिक कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों के कारण सूरत महानगरपालिका की दूसरी जनरल बोर्ड बैठक फिलहाल टल सकती है, जिसके चलते विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के गठन और उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी देरी होने की संभावना है।

नगर निगम के भीतर चल रही चर्चाओं के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक दूसरी जनरल बैठक आयोजित किए जाने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यापक तैयारियों और प्रशासनिक व्यस्तताओं को देखते हुए अब यह बैठक अगले सप्ताह के अंत या उससे भी बाद में आयोजित की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो नगर निगम की विभिन्न स्थायी और विषयगत समितियों के गठन की प्रक्रिया भी कुछ समय के लिए आगे खिसक जाएगी।

दरअसल, सूरत महानगरपालिका में हाल ही में नए बोर्ड का गठन हुआ है और 28 मई को आयोजित पहली जनरल बोर्ड बैठक में महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हुआ था। इस बैठक के साथ ही लंबे समय से जारी प्रशासकीय शासन का औपचारिक अंत हुआ और निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में नगर प्रशासन की जिम्मेदारी वापस आई। इसके बाद पार्षदों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच यह उम्मीद थी कि दूसरी जनरल बैठक में नगर निगम की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया जाएगा, जिससे प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक सक्रिय हो सके।

नगर निगम में कुल 12 महत्वपूर्ण समितियों का गठन होना है, जिनमें पब्लिक वर्क्स कमेटी, ड्रेनेज कमेटी, स्लम इम्प्रूवमेंट कमेटी, टाउन प्लानिंग कमेटी, हेल्थ कमेटी, वाटर वर्क्स कमेटी तथा अन्य विषयगत समितियां शामिल हैं। ये समितियां शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, जलापूर्ति, शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन समितियों का गठन नगर निगम की प्रशासनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

हालांकि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे ने फिलहाल सभी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा ध्यान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने पर केंद्रित है। नगर निगम के अनेक अधिकारी और कर्मचारी आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। ऐसे में जनरल बोर्ड बैठक आयोजित करने और समिति गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हाल ही में जिला कलेक्टर कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, गुजरात सरकार के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मंच संचालन, अतिथि प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े कार्यों में नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत, सौंदर्यीकरण, पार्किंग, यातायात नियंत्रण और आयोजन स्थल की तैयारियों में भी निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि फिलहाल निगम प्रशासन का पूरा ध्यान इसी दिशा में केंद्रित है।

नगर निगम की समितियों के गठन में संभावित देरी का असर उन पार्षदों पर भी पड़ सकता है जो विभिन्न समितियों में अध्यक्ष या सदस्य पद प्राप्त करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाजपा के भीतर भी विभिन्न समितियों के पदों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और कई पार्षद संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे में समिति गठन में देरी से राजनीतिक प्रतीक्षा और बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई नगर सरकार के गठन के बाद समिति अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियां स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेंगी। इसलिए इन समितियों के गठन को लेकर भाजपा संगठन और नगर निगम दोनों स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे के कारण फिलहाल इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित रखना प्रशासनिक आवश्यकता माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरत पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त रहेगा। वे सबसे पहले हजीरा स्थित एलएंडटी प्लांट का दौरा करेंगे, जहां औद्योगिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रस्तावित हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कारण सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

फिलहाल नगर निगम के भीतर यह लगभग तय माना जा रहा है कि दूसरी जनरल बोर्ड बैठक प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न समितियों के गठन और पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी उसी के बाद आगे बढ़ेगी। ऐसे में शहर के विकास कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों के गठन के लिए पार्षदों और प्रशासन को कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा संपन्न होते ही नगर निगम की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया को गति दी जाएगी और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज, यूपीआई ने बनाया नया इतिहास; मई में 29.9 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेनदेन

नई दिल्ली। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक बार फिर नए मुकाम पर पहुंच गई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने मई 2026 में लेनदेन के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मई महीने में यूपीआई के माध्यम से 29.90 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जबकि कुल ट्रांजैक्शन की संख्या 23.2 अरब तक पहुंच गई। यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक प्रदर्शन माना जा रहा है और इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत तेजी से नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल भुगतान आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि देश में स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, डिजिटल भुगतान को लेकर लोगों के बढ़ते विश्वास तथा सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने यूपीआई को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। आज स्थिति यह है कि महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक लोग चाय की दुकान, सब्जी बाजार, किराना स्टोर, टैक्सी, ऑनलाइन खरीदारी और बड़े व्यावसायिक लेनदेन तक के लिए यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं।

एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में यूपीआई के माध्यम से 29.03 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि मई में यह आंकड़ा बढ़कर 29.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी तरह लेनदेन की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि केवल सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान के बढ़ते वर्चस्व का संकेत भी है। विश्लेषकों के अनुसार मई महीने में गर्मी की छुट्टियों के कारण पर्यटन और यात्रा गतिविधियों में आई तेजी ने भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने होटल बुकिंग, रेल और हवाई टिकट, ऑनलाइन खरीदारी तथा मनोरंजन सेवाओं के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान टिकट बुकिंग, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स और अन्य उपभोक्ता खर्चों में हुई बढ़ोतरी ने भी यूपीआई लेनदेन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो यूपीआई की वृद्धि और भी प्रभावशाली नजर आती है। मई 2025 में यूपीआई के माध्यम से 25.14 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि मई 2026 में यह आंकड़ा लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 29.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी प्रकार लेनदेन की संख्या भी पिछले वर्ष के 18.67 अरब से बढ़कर 23.2 अरब हो गई, जो लगभग 24 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्धि बताती है कि डिजिटल भुगतान अब केवल सुविधा का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भुगतान प्रणाली से जुड़ी रिपोर्ट भी यूपीआई के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई लेनदेन का औसत आकार लगातार कम हुआ है। वर्ष 2021 में जहां एक औसत यूपीआई ट्रांजैक्शन का मूल्य 1,848 रुपये था, वहीं 2025 तक यह घटकर 1,313 रुपये रह गया। विशेषज्ञ इसे नकारात्मक संकेत नहीं मानते, बल्कि इसे यूपीआई के व्यापक जनसामान्य तक पहुंचने का प्रमाण बताते हैं। उनका कहना है कि अब लोग केवल बड़े भुगतान ही नहीं, बल्कि छोटी-छोटी दैनिक जरूरतों के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि औसत ट्रांजैक्शन मूल्य घटा है, लेकिन कुल लेनदेन संख्या और कुल भुगतान मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं।

यूपीआई की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी है। भारत की यह स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली अब केवल देश तक सीमित नहीं रही। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, मॉरीशस सहित सात देशों में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधा उपलब्ध है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों, व्यापारियों और पर्यटकों को भुगतान करने में बड़ी सुविधा मिल रही है। सरकार और एनपीसीआई अन्य देशों के साथ भी इस प्रणाली के विस्तार को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीआई ने भारत में वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। जिन लोगों के पास पहले डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं तक सीमित पहुंच थी, वे भी अब मोबाइल फोन के माध्यम से सुरक्षित और त्वरित भुगतान कर पा रहे हैं। इससे छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, स्वरोजगार से जुड़े लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विशेष लाभ मिला है।

डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ी है। नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होने से कर प्रणाली को मजबूती मिली है और वित्तीय गतिविधियों का बेहतर रिकॉर्ड उपलब्ध हो रहा है। सरकार लंबे समय से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देती रही है और यूपीआई की उपलब्धियां इस दिशा में बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही हैं।

बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि आने वाले वर्षों में यूपीआई का दायरा और अधिक विस्तृत होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भुगतान समाधान, सीमा-पार भुगतान सेवाएं, ऑफलाइन यूपीआई भुगतान और नए डिजिटल वित्तीय उत्पाद इस प्रणाली को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। जिस गति से यूपीआई का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल डिजिटल भुगतान बाजारों में अपनी स्थिति और मजबूत करता दिखाई दे रहा है।

मई 2026 के रिकॉर्ड आंकड़े केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस डिजिटल परिवर्तन की कहानी हैं जिसने करोड़ों भारतीयों के भुगतान करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। बढ़ते लेनदेन, व्यापक स्वीकार्यता और वैश्विक विस्तार के साथ यूपीआई अब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है।

मानसून से पहले मनपा की तैयारियों पर उठे सवाल, समीक्षा बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली पर फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा

सूरत। मानसून की दस्तक से पहले सूरत महानगरपालिका की तैयारियों की हकीकत उस समय सामने आ गई जब प्री-मानसून समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अधूरे कार्यों, धीमी प्रगति और लापरवाह रवैये को लेकर जमकर घेरा। शहर में हर वर्ष होने वाली जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों को देखते हुए बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विभागों की तैयारियां अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर महापौर से लेकर स्टैंडिंग कमेटी के पदाधिकारियों तक ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि यदि मानसून के दौरान शहर में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। सूरत महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता महापौर मायाबेन मावाणी ने की, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजन पटेल ने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में शहर के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों, ड्रेनेज नेटवर्क, जल निकासी व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं तथा मिंधोला नदी क्षेत्र से जुड़े कार्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

बैठक में सबसे गंभीर मुद्दा डायमंड बर्स के पीछे स्थित मिंधोला नदी के मुहाने के पास बने जिंगा तालाबों का रहा। अधिकारियों की रिपोर्ट से पता चला कि इन तालाबों को हटाने का कार्य छह महीने पहले शुरू किए जाने के बावजूद अब तक मात्र पांच प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। यह जानकारी सामने आते ही जनप्रतिनिधियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री ने छह माह पूर्व ही इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि यह क्षेत्र मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की समस्या का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बावजूद कार्य की गति बेहद धीमी रहना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर छह महीने के लंबे समय के बावजूद कार्य में इतनी कम प्रगति क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से भी कई सदस्य संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना था कि यदि इसी गति से कार्य चलता रहा तो आगामी मानसून में फिर से वही समस्याएं सामने आ सकती हैं जिनसे स्थानीय नागरिक वर्षों से जूझ रहे हैं। बैठक में खाड़ी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए गठित विशेष समिति की निष्क्रियता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में गठित इस समिति का उद्देश्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों की निगरानी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना था। हालांकि बैठक में बताया गया कि शुरुआती बैठकों के बाद समिति की गतिविधियां लगभग ठप पड़ गईं और कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। इस पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए गठित समितियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अगले सप्ताह जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त के बीच विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बाढ़ नियंत्रण से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने अपेक्षा जताई कि इस बैठक के बाद जमीनी स्तर पर भी ठोस कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए।

समीक्षा के दौरान शहर के विभिन्न जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग बोर निर्माण की प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। बताया गया कि कई जोनों में कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वर्षा जल संचयन और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किए बिना जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसलिए सभी जोनों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल ने मानसून के दौरान संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए डी-वाटरिंग पंप, ड्रेनेज सफाई उपकरण, आपदा राहत संसाधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों को देखते हुए इस बार किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभागों को पहले से ही तैयारी पूरी करनी होगी।

बैठक का सबसे चर्चित पहलू अधिकारियों की तैयारी को लेकर रहा। कई विभागों के अधिकारी आवश्यक आंकड़ों, अद्यतन जानकारी और प्रगति रिपोर्ट के बिना बैठक में पहुंचे थे। जब जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति के बारे में सवाल पूछे तो कुछ अधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर राजन पटेल ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकें केवल औपचारिकता नहीं हैं और अधिकारियों को पूरी तैयारी तथा तथ्यात्मक जानकारी के साथ उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि अधिकारी स्वयं अपने विभागों की स्थिति से पूरी तरह अवगत नहीं होंगे तो शहर की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की मांग की और कहा कि महत्वपूर्ण बैठकों में अधूरी जानकारी के साथ पहुंचना गंभीर लापरवाही माना जाना चाहिए।

सूरत टेक्सटाइल मार्केट में चुनावी सरगर्मियां तेज 18 जुलाई को चुनी जाएगी नई प्रबंधन समिति

सूरत। देश के सबसे बड़े वस्त्र व्यापारिक केंद्रों में शामिल सूरत टेक्सटाइल मार्केट में एक बार फिर चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट को-ऑपरेटिव शॉप्स एंड वेयरहाउसेस सोसाइटी लिमिटेड की नई प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। रविवार को आयोजित इलेक्शन कमिटी की महत्वपूर्ण बैठक में वर्ष 2026 से 2031 तक के कार्यकाल के लिए 20 सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मार्केट के हजारों व्यापारियों और सदस्यों के बीच चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मार्केट कार्यालय में आयोजित बैठक में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इलेक्शन कमिटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए आगामी 18 जुलाई 2026 को मतदान कराने की घोषणा की। समिति का कहना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराया जाएगा, ताकि सभी पात्र सदस्यों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का समान अवसर मिल सके।

सूरत टेक्सटाइल मार्केट न केवल सूरत बल्कि देश के वस्त्र व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहां हजारों व्यापारी, दुकानदार और गोदाम संचालक अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते हैं। ऐसे में सोसायटी की प्रबंधन समिति का चुनाव व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नई समिति अगले पांच वर्षों तक मार्केट के प्रशासन, विकास कार्यों, सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार रखेगी।

बैठक में चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव से संबंधित सभी नियम, पात्रता मानदंड, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके लिए अलग से विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जिससे सभी सदस्य समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें। जानकारों का मानना है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न व्यापारिक समूहों और संभावित उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मार्केट के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और समूहों के बीच समर्थन जुटाने की कवायद भी शुरू हो सकती है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी कई प्रमुख व्यापारी और अनुभवी पदाधिकारी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बैठक में चीफ इलेक्शन ऑफिसर अशोक जैन, इलेक्शन ऑफिसर गुरमुख कुंगवानी तथा इलेक्शन ऑफिसर महेंद्रपाल खुराना विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे चुनाव संबंधी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाओं में भाग लें।

सूरत टेक्सटाइल मार्केट की यह चुनाव प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल उद्योग कई नई चुनौतियों और अवसरों के दौर से गुजरने वाला है। डिजिटल कारोबार, ई-कॉमर्स, निर्यात प्रतिस्पर्धा, बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और व्यापारिक सुरक्षा जैसे मुद्दे नई समिति के सामने प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। ऐसे में व्यापारी वर्ग ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहेगा जो मार्केट के विकास और व्यापारियों के हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। 18 जुलाई को होने वाले मतदान के जरिए 20 सीटों के लिए नए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही सूरत टेक्सटाइल मार्केट में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का औपचारिक आगाज हो गया है और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

बदलती जीवनशैली बना रही घुटनों को कमजोर, युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही समस्या

सूरत। आधुनिक जीवनशैली, घटती शारीरिक सक्रियता और बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच घुटनों की बीमारियां एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। कभी बढ़ती उम्र से जुड़ी मानी जाने वाली यह समस्या अब युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के लोगों में भी तेजी से देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले एक दशक में घुटनों से संबंधित रोगों के मामलों में लगभग पांच गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो बदलती जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती लापरवाही का स्पष्ट संकेत है। इसी विषय पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) की पब्लिक हेल्थ कमेटी द्वारा आयोजित लोक जागृति हेल्थ सीरीज़ के 41वें कार्यक्रम में घुटनों के दर्द और उसके आधुनिक उपचार पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित सीड्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक एवं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. चिन्मय देसाई ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में भाग लेते हुए घुटनों की समस्याओं, उनके कारणों और उपचार के आधुनिक विकल्पों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत में एसजीसीसीआई के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि हेल्थ सीरीज़ का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को विभिन्न बीमारियों की रोकथाम और समय पर उपचार के प्रति शिक्षित करना है। उन्होंने पब्लिक हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन पारुलबेन वडगामा और उनकी टीम के प्रयासों की भी सराहना की।

अपने व्याख्यान में डॉ. चिन्मय देसाई ने बताया कि घुटनों की समस्याओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। बढ़ता मोटापा, लंबे समय तक बैठे रहने की आदत, नियमित व्यायाम का अभाव, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन और असंतुलित जीवनशैली प्रमुख कारणों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले घुटनों का आर्थराइटिस सामान्य रूप से 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में देखा जाता था, लेकिन अब 30 से 40 वर्ष की आयु में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ मामलों में किशोरों और युवाओं में भी घुटनों की समस्याएं सामने आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि घुटनों के दर्द को सामान्य रूप से तीन चरणों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में दर्द कभी-कभी होता है और आराम करने से ठीक हो जाता है। मध्यम अवस्था में दर्द नियमित रूप से महसूस होने लगता है, हालांकि व्यक्ति की दैनिक गतिविधियां बहुत अधिक प्रभावित नहीं होतीं। जबकि उन्नत अवस्था में दर्द इतना अधिक बढ़ जाता है कि चलना-फिरना, सीढ़ियां चढ़ना और सामान्य दिनचर्या तक प्रभावित हो जाती है। डॉ. देसाई के अनुसार घुटनों की समस्या से बचाव और उपचार का सबसे प्रभावी तरीका जीवनशैली में सुधार है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी उपचार की आधारशिला है, क्योंकि इससे घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने कुल शरीर के वजन का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा भी कम कर ले, तो घुटनों पर पड़ने वाला भार कई गुना तक घटाया जा सकता है, जिससे दर्द और सूजन में उल्लेखनीय राहत मिल सकती है। जब दवाओं, व्यायाम और फिजियोथेरेपी से पर्याप्त लाभ नहीं मिलता, तब चिकित्सक स्टेरॉयड इंजेक्शन, हाइलूरोनिक एसिड इंजेक्शन और पीआरपी (प्लेटलेट रिच प्लाज्मा) थेरेपी जैसे विकल्प अपनाते हैं।

53 लाख के आभूषणों से भरा बैग लौटाकर सीआईएसएफ ने जीता भरोसा, सूरत एयरपोर्ट पर ईमानदारी की मिसाल

सूरत। ऐसे समय में जब अक्सर खोया हुआ सामान वापस मिलने की उम्मीद बेहद कम रह जाती है, सूरत एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने अपनी ईमानदारी, सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसने न केवल एक यात्री को बड़ी राहत दी बल्कि सुरक्षा बलों के प्रति लोगों का विश्वास भी और मजबूत कर दिया। सीआईएसएफ कर्मियों ने 53.34 लाख रुपये मूल्य के बहुमूल्य आभूषणों और नकदी से भरा एक लावारिस बैग उसके वास्तविक मालिक को सुरक्षित लौटाकर अपनी पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है।

घटना 1 जून 2026 की है। सूरत एयरपोर्ट के आगमन द्वार के बाहर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को एक हैंडबैग लावारिस अवस्था में पड़ा मिला। एयरपोर्ट जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध या बिना मालिक के सामान को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में जवानों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए बैग को अपने कब्जे में लिया और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उसकी जांच और मालिक की पहचान की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद सीआईएसएफ टीम ने बैग से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके स्वामी का पता लगाने का प्रयास किया। जांच में सामने आया कि बैग शैलेश प्रेमप्रकाश गुप्ता नामक यात्री का है, जो बेंगलुरु से सूरत आने वाली उड़ान संख्या IX-2052 से यात्रा कर सूरत पहुंचे थे। यात्रा की जल्दबाजी और अन्य कारणों से वह अपना हैंडबैग एयरपोर्ट परिसर में ही भूल गए और सीधे घर चले गए। बैग मिलने के बाद सीआईएसएफ अधिकारियों ने पूरी सावधानी के साथ यात्री से संपर्क स्थापित किया और उन्हें एयरपोर्ट बुलाया। आवश्यक दस्तावेजों, पहचान पत्रों और अन्य औपचारिकताओं का सत्यापन करने के बाद ही बैग उन्हें सौंपा गया। जब बैग की जांच की गई तो उसमें लगभग 53.34 लाख रुपये मूल्य के बहुमूल्य आभूषण और करीब 30 हजार रुपये नकद सुरक्षित पाए गए। इतनी बड़ी राशि और कीमती सामान सुरक्षित मिलने पर यात्री ने राहत की सांस ली। अपना बहुमूल्य सामान सुरक्षित वापस मिलने के बाद शैलेश प्रेमप्रकाश गुप्ता ने सीआईएसएफ के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि सीआईएसएफ के जवान समय रहते सतर्कता नहीं दिखाते तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की ईमानदारी और जिम्मेदारी की खुले दिल से प्रशंसा की तथा एक वीडियो संदेश के माध्यम से भी अपना धन्यवाद व्यक्त किया। यह घटना केवल एक खोया हुआ बैग लौटाने की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि देश के हवाई अड्डों पर तैनात सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता और निष्ठा के साथ निभाते हैं। सीआईएसएफ का दायित्व केवल सुरक्षा जांच और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा, सहायता और विश्वास को बनाए रखना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।

सूरत एयरपोर्ट पर हुई यह घटना सीआईएसएफ के ध्येय वाक्य "सुरक्षा के साथ सेवा" को पूरी तरह चरितार्थ करती है। सुरक्षा बल के जवान प्रतिदिन लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऐसी मानवीय जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यही कारण है कि देशभर के हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण संस्थानों में सीआईएसएफ की कार्यशैली को अत्यंत भरोसेमंद माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं आम नागरिकों में सुरक्षा एजेंसियों के प्रति सकारात्मक विश्वास पैदा करती हैं। जब लाखों रुपये मूल्य का सामान बिना किसी क्षति के उसके मालिक तक पहुंचाया जाता है, तो यह केवल कर्तव्य पालन नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और ईमानदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण बन जाता है।

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 : साइबर क्राइम के खिलाफ गुजरात पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक

▸▸ 2289 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 913 म्यूल अकाउंट के विरुद्ध कार्रवाई, 565 प्राथमिकी दर्ज और 638 की गिरफ्तारी

▸▸ आरबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से म्यूल अकाउंट के खिलाफ करेगा कार्रवाई, खातों के लेनदेन को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साइबर क्राइम के खिलाफ भारत सरकार एक्शन मोड में, गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अभियान को मिली मजबूती

गांधीनगर : गुजरात के नागरिकों को साइबर क्राइम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों की पसीने की कमाई साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से बचाने और साइबर क्राइम में संलिप्त अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से राज्य पुलिस ने विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन चलाकर निर्णायक कार्रवाई की है।

इस व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में पूरे राज्य में एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया। गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीई) द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में म्यूल खातों के खिलाफ कार्रवाई करके अलग-अलग मामलों में कुल 2289 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया गया है।

क्या है म्यूल अकाउंट?

म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी धोखाधड़ी से हासिल धन को प्राप्त करने, ट्रांसफर करने और मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) करने के लिए करते हैं। जिस व्यक्ति के पास यह अकाउंट होता है, उसे 'मनी म्यूल' कहा जाता है। साइबर अपराधी इन खातों की मदद से पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। गुजरात पुलिस ने ऐसे म्यूल खातों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही यह ऑपरेशन चलाया है। साइबर अपराधों में म्यूल खातों का इस्तेमाल जानबूझकर या अनजाने में किया जाता है।

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0

गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीई) ने वर्ष 2025 में ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 चलाया था। इस ऑपरेशन में सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज प्रमुखों, लोकल क्राइम ब्रांच के निरीक्षकों और साइबर पुलिस स्टेशनों को शामिल किया गया। इस ऑपरेशन की दैनिक निगरानी करते हुए मुख्यालय ने प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। गुजरात पुलिस की टीम ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी), समन्वय पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त डेटा को एकत्र किया। इस डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके फील्ड पर मिली शिकायतों के लिए एक सपोर्ट टीम बनाई गई। सभी बैंकों को रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए निर्देश देकर उचित तालमेल किया गया। इस प्रकार, डेटा इंटेलिजेंस और उचित तालमेल के माध्यम से, गुजरात पुलिस ने म्यूल अकाउंट की आपराधिक गतिविधि की जड़ों पर प्रहार करके अभूतपूर्व नतीजे हासिल करने में सफलता प्राप्त की है।

ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 की मुख्य उपलब्धियां :-

- कुल एफआईआर : 565
- कुल गिरफ्तारी : 638
- म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई : 193
- अपराधों की पहचान : 4052 (गुजरात में 491)
- आर्थिक धोखाधड़ी का मूल्य : 2289 करोड़ रुपए

ऑपरेशन के कारण एटीएम और चेक द्वारा आहरण (विड्रॉल) में देखा गया बदलाव :-

- चेक द्वारा आहरण में 75 फीसदी कमी
- मासिक चेक आहरण 126 करोड़ से घटकर 25 करोड़ रुपए हुआ, जो 80 फीसदी की कमी दिखाता है
- पहली लेयर के म्यूल अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट, जहां सबसे पहले पैसे जमा होते हैं, की संख्या में अगस्त से दिसंबर 2025 तक 30 फीसदी की कमी
- सितंबर से दिसंबर 2025 तक एटीएम आहरण में 66 फीसदी की कमी

आरबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से म्यूल अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा

म्यूल अकाउंट के खिलाफ इस अभियान को और अधिक कार्यकुशल और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्गदर्शन में इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (आईडीपीआईसी) के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उपयोग से रिस्क स्कोरिंग प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक लेनदेन को लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जेगा, जिससे संदिग्ध अकाउंट की पहचान की जा सके। इस स्कोर के आधार पर विभिन्न बैंक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। आईडीपीआईसी को इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गी है। संदिग्ध अकाउंट से संबंधित जानकारी को विभिन्न बैंकों के बीच साझा करने के लिए 'म्यूलहंटर डॉट एआई' (mulehunter.ai) नामक रजिस्ट्री भी बनाई गई है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की है और नागरिकों से डिजिटल अरेस्ट जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के खिलाफ बिना डरे अधिक जागरूकता के साथ डिजिटल प्रक्रियाएं करने को कहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अभी 100 करोड़ से भी अधिक है, जो 11 वर्ष पहले 25 करोड़ थी। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि और संसद से लेकर पंचायतों तक 'भारतनेट' से जुड़ना, डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भी 16 फीसदी की वृद्धि हुई है। भारत नेट परियोजना के तहत 11 वर्ष पहले केवल 546 पंचायतें जुड़ी थीं, लेकिन आज 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इस परियोजना से जुड़ चुकी हैं। इसी प्रकार, यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार साइबर सुरक्षा अब केवल आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ गया है। इसलिए, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के आयामों को मजबूती से सुरक्षित करना और डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

काकरापार खाड़ी पर अवैध दबाव के कारण सूरत में हर साल बाढ़ आती है, प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत शहर से होकर गुजरने वाली काकरा खाड़ी के दोनों किनारों पर निर्माणकर्ताओं द्वारा डाले गए अवैध दबाव के कारण हर साल खाड़ी में बाढ़ आती है। इससे सूरत शहर के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सूरत शहर से होकर गुजरने वाली काकरा खाड़ी के दोनों किनारों पर श्याम संगी के टेक्सटाइल कुम्भरिया और सारथी टेक्सटाइल कुम्भरिया के अवैध निर्माण के साथ-साथ लिंबायत जोन और सूडा के अवैध निर्माण के कारण भी हर साल काकरा खाड़ी में बाढ़ आती है।

खाड़ी के दोनों किनारों पर स्थित बाजारों के दबाव के कारण जल प्रवाह बाधित होता है। इसके परिणामस्वरूप, लिंबायत, पर्वत पाटिया, पूना और कुम्भरिया जैसे निचले इलाकों में पानी वापस बह जाता है। भारी बारिश होते ही जलभराव के कारण उपरोक्त खाड़ियाँ उफान पर आ जाती हैं। साथ ही, मीठी और कोयली खाड़ियों का जल स्तर भी इस खाड़ी के जल के साथ बढ़ जाता है। इससे पहले, सूरत शहर के सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल डी. मेवाड़ा ने इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। इसके बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने जल निकासी विभाग (SUD) के अधिकारियों को नोटिस भेजा था। लेकिन तत्कालीन SUD अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके कारण, आम जनता को हर साल खाड़ी की बाढ़ का सामना करना पड़ता है। हर साल उनके घरों और संपत्ति को नुकसान होता है और साथ ही, इन क्षेत्रों के छोटे-बड़े व्यवसायों को भी भारी आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार, SUD अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरा सूरत शहर प्रभावित होता है। सूरत शहर के कई लोग व्यापार के लिए इन नालों को पार करके एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होते ही ये नाले उफान पर आ जाते हैं।

जिसके कारण आम जनता के साथ-साथ लिंबायत और मीठी खाड़ी क्षेत्रों को भी हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों को नाले के दोनों किनारों पर बने अवैध दबाव को हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाढ़ का पानी आसानी से बह सके और जनता को राहत मिल सके। बाढ़ आने पर ही नगर निगम व्यवस्था सक्रिय होती है और फिर एक साल तक कुंभकर्ण की नींद में सोती रहती है। सूरत नगर निगम के नगर आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नाले के दोनों किनारों पर बने दबाव को तुरंत हटाना चाहिए। सूरत नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माणों को हटाने में सक्षम हैं, तो इन बाजारों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को हटाने से उन्हें कौन रोक रहा है? इससे इस नगर निगम के उच्च अधिकारियों के हाथ तो काले नहीं पड़ गए, है ना?

सूरत में अधूरे निर्माण परियोजनाओं में व्यापारियों के करोड़ों रुपये फंसे, न्याय के लिए कानूनी लड़ाई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत की छवि धूमिल हो रही है। ऐसा लगता है कि सूरत की छवि को बिल्डरों द्वारा धूमिल किया जा रहा है क्योंकि शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सहारा दरवाजा, कडोदरा, सरोली, टेक्सटाइल मार्केट, मागोब, पुणे, पर्वत पाटिया, लिंबायत और पूरे शहर में कई बिल्डरों द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाएं लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं और उन पर धूल जम रही है। ये परियोजनाएं ऐसी स्थिति में हैं जहां उनका कोई मालिक नहीं है और इन धूल भरे प्रोजेक्टों में व्यापारियों द्वारा दुकानों, गोदामों या फ्लैटों को बुक करने के लिए बिल्डरों को दी गई अग्रिम राशि फंसी हुई है। न तो बिल्डरों ने इसे वापस किया है और न ही व्यापारियों द्वारा बुक की गई दुकानों, गोदामों या फ्लैटों का कब्जा दिया है।

हमेशा की तरह, बिल्डर खुलेआम उन व्यापारियों को धमकाते हैं जो ऐसे कई धूल भरे प्रोजेक्टों में निवेश किए गए अपने पैसे वापस लेने वाले होते हैं। वे उनसे कहते हैं कि अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए, तो उसमें से 30% से 40% काटकर ही वापस मिलेगा। बाकी पैसा आप जहां चाहें जा सकते हैं। पुलिस के पास जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं या जिसके पास चाहें जा सकते हैं। बिल्डरों द्वारा नियुक्त असामाजिक तत्व खुलेआम व्यापारियों से यह कहते हैं। इस प्रकार, बिल्डर प्रोजेक्ट बुक करने वाले व्यापारियों को आरी की तरह काट रहे हैं। जिस प्रकार आरी लकड़ी को काटती हुई आती-जाती है, उसी प्रकार व्यापारी भी दुकानों, गोदामों या फ्लैटों के लिए दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज नहीं चुकाते और न ही पूरी मूल राशि लौटाते हैं, भले ही वह राशि लंबे समय तक बिल्डर के पास पड़ी रहे। इसके अलावा, वे राशि में से 30% से 40% काटकर वापस करने की बात करते हैं, जिससे ग्राहकों को आर्थिक और मानसिक क्षति होती है, और कभी-कभी शारीरिक क्षति भी होती है।

ऐसे बिल्डर कई कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें आरईआरए का पालन न करना, अनुमति पत्र न होना, योजनाओं को मंजूरी न मिलना, परियोजनाओं को अधूरा छोड़ना, व्यापारियों से अग्रिम राशि लेना और उसे ऐसे पत्र या डायरी में हस्ताक्षर करना जिसे पढ़ा न जा सके, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बिल्डरों द्वारा कई अन्य अवैध कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके कारण सूरत शहर में बिल्डरों की कई अधूरी परियोजनाएं धूल में पड़ी हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। ये बिल्डर निर्माण व्यवसाय में हैं। व्यापारियों ने इन्हें किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं दी है कि यदि आप परियोजना शुरू करेंगे तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यह बिल्डरों का व्यवसाय है। और इस व्यवसाय में कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं। यदि कीमत बढ़ती है, तो बिल्डर परियोजना बुक करने वाले व्यापारियों से तुरंत अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं। फिर यदि कीमत घटती है, तो मूल रूप से तय की गई राशि में कोई कमी क्यों नहीं की जाती? इस तरह बिल्डरों द्वारा व्यापारियों को धोखा दिया जा रहा है। योजना की मंजूरी से लेकर लीव लेटर प्राप्त होने तक, यानी 12 से 15 वर्षों तक, जब तक बीयूसी प्राप्त नहीं हो जाता, यदि दलालों के माध्यम से बुकिंग करके परियोजनाओं में निवेश करने वाले व्यापारियों का पैसा पंद्रह दिनों की समय सीमा के भीतर वकीलों के माध्यम से कानूनी रूप से नहीं निकाला जाता है, तो आरईआरए कानून के तहत दलालों और बिल्डरों के खिलाफ अदालत के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिन व्यापारियों ने खाली नोट या सिर्फ डायरी पर लेन-देन किया है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण नोट होने पर भी उसे प्रयोगशाला रिपोर्ट के लिए एफएसएल (वित्तीय सेवा प्रदाता) भेजा जाएगा। पुलिस या असामाजिक तत्वों को क्यों न शामिल किया जाए जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और व्यापारियों को न्याय मिलेगा।

भारत-ओमान आर्थिक रिश्तों को मिली नई रफ्तार, सीईपीए लागू होते ही तरजीही शुल्क पर रवाना हुई पहली निर्यात खेप

नई दिल्ली। भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) सोमवार, एक जून 2026 से औपचारिक रूप से लागू हो गया। समझौते के प्रभावी होते ही भारत ने तरजीही शुल्क व्यवस्था के तहत ओमान के लिए अपनी पहली निर्यात खेप रवाना कर दी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बंदरगाहों से भेजी गई इस पहली खेप में कृषि उत्पादों के साथ रत्न एवं आभूषण शामिल हैं। इस घटनाक्रम को भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते के लागू होने के साथ ही भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में बेहतर पहुंच मिलने लगेगी। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय व्यापार को मजबूत आधार मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह समझौता केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निवेश, रोजगार और उद्योगों के विस्तार के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर को भारत की निर्यात नीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सीईपीए के लागू होने से भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में शुल्क संबंधी राहत मिलेगी और कई उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त होगी। इससे भारत के विभिन्न औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उनके अनुसार यह समझौता विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, चमड़ा उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, समुद्री उत्पाद, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, खेल सामग्री तथा कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसर लेकर आएगा। गोयल ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत लगातार नए बाजारों की तलाश कर रहा है। ऐसे समय में ओमान के साथ यह समझौता भारतीय उत्पादों को खाड़ी क्षेत्र में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और अधिक गहरा होगा तथा व्यापारिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार का मानना है कि सीईपीए का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नए निर्यात अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा किसानों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप इकाइयों और आयुष क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।

समझौते के तहत कई उत्पादों को शून्य शुल्क या रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातकों की लागत कम होगी और वे ओमान के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने उत्पाद उपलब्ध करा सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क में कमी से भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देश के उत्पादन और रोजगार पर भी पड़ेगा। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र भारतीय निर्यातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। ओमान के साथ आर्थिक संबंधों के मजबूत होने से भारत को पश्चिम एशिया में अपनी व्यापारिक उपस्थिति और सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा। ओमान लंबे समय से भारत का विश्वसनीय आर्थिक सहयोगी रहा है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध काफी पुराने हैं। अब सीईपीए के माध्यम से इन संबंधों को संस्थागत और व्यापक आधार मिल गया है। पीयूष गोयल ने इस अवसर पर भारत की व्यापक व्यापारिक रणनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक स्तर पर नए व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भी बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ शेष मुद्दों पर चर्चा जारी है और जल्द ही इस दिशा में भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। ओमान वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 11.18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। अब सीईपीए लागू होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद निकट भविष्य में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह दोनों देशों के आर्थिक सहयोग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। व्यापार के विस्तार के साथ-साथ निवेश, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भी नई साझेदारियां विकसित हो सकती हैं। भारतीय उद्योग जगत ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों का मानना है कि इससे निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे और भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ेगी।

अहमदाबाद मंडल का मई 2026 में रिकॉर्ड प्रदर्शन: माल भाड़ा राजस्व 517.34 करोड़ पार,अहमदाबाद मंडल की बड़ी छलांग: माल लदान, राजस्व और यात्री सेवाओं में दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के परिचालन विभाग ने मई 2026 के महीने में माल लदान (फ्रेट लोडिंग), राजस्व सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सेवाओं के मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

वित्तीय एवं माल लदान (लोडिंग) की मुख्य विशेषताएं

राजस्व में वृद्धिः मंडल ने मई 2026 में 517.34 करोड़ रुपये का माल भाड़ा राजस्व अर्जित किया।

रिकॉर्ड लदानः इस महीने कुल 3.93 मिलियन टन (MT) माल का लदान किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 3.83 मिलियन टन की तुलना में 2.6% की वृद्धि दर्शाता है । इस दौरान प्रतिदिन औसतन 2639.48 वैगनों का लदान किया गया।

प्रमुख वस्तुएं (कमोडिटी): मई 2025 की तुलना में कई प्रमुख वस्तुओं के लदान में भारी उछाल देखा गया, जिसमें नमक (औद्योगिक नमक सहित) में +31.53%, उर्वरक (फर्टिलाइजर) में +13.02% और अन्य वस्तुओं में +22.64% की वृद्धि दर्ज की गई।

गांधीधाम क्षेत्र का नेतृत्वः माल लदान के मामले में गांधीधाम क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां प्रतिदिन औसतन 1936.97 वैगनों का लदान किया गया।

"कच्छ से कश्मीर" बिजनेस पहल

बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) के

प्रयासों से गांधीधाम क्षेत्र ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है । 5 मई 2026 को, मंडल ने "कच्छ-टू-कश्मीर" माल परिवहन पहल के तहत 20 BCN वैगनों में भीमासर (BMSR) से बारी ब्राह्मण (BBMN) और अनंतनाग (ANT) के लिए खाद्य तेल की पहली खेप भेजी गई।

बुनियादी ढांचा विकास और परिचालन क्षमता

नई वाई-कनेक्टिविटी (Y-Connectivity): चांदखेड़ा-गांधीग्राम वाई-कनेक्टिविटी के चालू होने के बाद पहली बार इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ । 29 मई 2026 को ट्रेन संख्या 09257 ने गांधीग्राम (GG) से चांदखेड़ा रोड के बीच पहला सफल संचालन किया गया।

लॉन्ग हॉल और क्रैक ट्रेनेंः मंडल ने इस महीने रिकॉर्ड 149 लॉन्ग-हॉल ट्रेनें चलाईं, जो मई 2025 की 28 ट्रेनों की तुलना में 432.14% की भारी वृद्धि है। इसके साथ ही, महीने के दौरान 1720 क्रैक ट्रेनों का भी संचालन किया गया । डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) इंटरचेंजः डीएफसी पॉइंट्स पर ट्रेनों का इंटरचेंज 7.43% बढ़कर औसतन 88.19 ट्रेनें प्रतिदिन हो गया, जो मई 2025 में 82.09 ट्रेनें प्रतिदिन था ।

अवरोधों को हटानाः परिचालन को सुगम बनाने के लिए 4 प्रमुख अवरोधों को स्थाई रूप से समाप्त किया गया । इसमें रोड अंडर ब्रिज (RUB) के माध्यम से राधनपुर-पिपली सेक्शन के बीच लेवल क्रॉसिंग (LC) 101 को हटाना और सनोसरा-नलिया सेक्शन में पुल संख्या 331 और 337 पर गति प्रतिबंधों (SR) में ढील देकर गति 70 किमी प्रति घंटा करना शामिल है ।

यात्री और कोचिंग ट्रेनों की सफलता

समयपालनबद्धता (Punctuality): मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालनबद्धता में सुधार हुआ है और यह मई 2025 के 91.06% से बढ़कर मई 2026 में 93.12% पर पहुंच गई है।

अतिरिक्त कोच जोड़नाः यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों में 434 अतिरिक्त कोच जोड़े गए।

नई ट्रेनों की शुरुआतः 23 मई 2026 को 19403/19404 भुज-दिल्ली-भुज दैनिक एक्सप्रेस शुरू की गई, जिसकी नियमित सेवा 23 मई 2026 से शुरू हुई।

19559/19560 ओखा-तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस की भी शुरुआत इस महीने की गई।

ट्रेनों का विस्तारः ट्रेन संख्या 20485/20486 जोधपुर-साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस का 22 मई 2026 से जैसलमेर (JSM) तक विस्तार किया गया ।

सेवाओं का नियमितीकरणः सुरेंद्रनगर-ध्रांगध्रा डेमू सेवा (ट्रेन संख्या 09259), जो पहले 'ट्रेन ऑन डिमांड' (TOD) के रूप में चल रही थी, उसे 12 मई 2026 से नियमित ट्रेन संख्या 79457 के रूप में बदल दिया गया है।

अहमदाबाद मंडल ने माल एवं यात्री परिवहन, सुरक्षा, अवसंरचना विकास तथा परिचालन दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पश्चिम रेलवे की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वरनामा – इटोला खंड पर ब्रिज के स्टील गर्डरों को पीएससी स्लैब से प्रतिस्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सूरत–वडोदरा रेलखंड के वरनामा एवं इटोला स्टेशनों के मध्य स्थित ब्रिज संख्या 567 {अप एवं डाउन लाइन) पर स्टील गर्डरों के स्थान पर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (PSC) स्लैब लगाने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह कार्य नियोजित रखरखाव ब्लॉकों के दौरान अत्यंत सावधानी एवं कुशलता के साथ संपन्न किया गया, जिससे रेल परिचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तीन स्पैन (प्रत्येक 12.2 मीटर) वाले इस पुल पर पीएससी स्लैब स्थापित करने के लिए 500 टन एवं 450 टन क्षमता वाली दो उच्च क्षमता की क्रेनों को एक साथ अलग-अलग स्पैन पर कार्य हेतु तैनात किया गया। बेहतर समन्वय एवं सुनियोजित कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप समस्त कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया गया तथा सभी ब्लॉक समय पर बहाल कर दिए गए।

पुराने स्टील गर्डरों के स्थान पर पीएससी स्लैब लगाए जाने से पुल की संरचनात्मक मजबूती एवं स्थायित्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही जंग लगने की समस्या में कमी आएगी, रखरखाव की आवश्यकता घटेगी तथा पुल की सेवा अवधि भी बढ़ेगी। यह उन्नयन रेल परिचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं दक्षता को और सुदृढ़ करेगा।

इन महत्वपूर्ण कार्यों की सफल पूर्णता पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल की सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक रेल अवसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल यात्रियों एवं माल परिवहन सेवाओं को और अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निरंतर अधोसंरचना उन्नयन एवं अनुरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दे रही है।